

स्मरणीय तथ्य :

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे और बड़े, औद्योगिक और व्यापारिक, निजी स्वामित्व वाली और सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं सहित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठन शामिल हैं। भारत में पायी जानेवाली आर्थिक संस्थाएं मुख्यतः दो भागों में विभाजित हैं: निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र।

निजी क्षेत्र:

निजी क्षेत्र निजी व्यक्तियों या समूहों के स्वामित्व वाले व्यवसायों से बना संगठन है। निजी क्षेत्र के भीतर विभिन्न संगठनात्मक संरचनाएँ पाई जा सकती हैं, जिनमें एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदु पारिवारिक व्यवसाय, सहकारी समितियाँ और कंपनियाँ शामिल हैं। ये व्यवसाय प्रत्यक्ष सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र:

इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे संगठन शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पूरी तरह या आंशिक रूप से केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व में हो सकती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विभिन्न रूप:

चूंकि सरकार विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में भाग लेती है, इसलिए उसे अपने विविध उद्यमों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग प्रकार के संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन अपने संचालन की प्रकृति और सरकार के साथ उनके संबंधों के आधार पर विभिन्न रूप के हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र संगठन के तीन प्राथमिक रूप हैं:

(i) विभागीय उपक्रम:

विभागीय उपक्रम मंत्रालय के अभिन्न विभागों के रूप में स्थापित हैं। ये उद्यम सरकार के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रालय के सीधे दायरे में संचालित होते हैं।

(ii) वैधानिक निगम/लोकनिगम/सार्वजनिक निगम :

वैधानिक निगम संसद के विशेष अधिनियमों के माध्यम से बनाए गए सार्वजनिक उद्यम हैं। संसद द्वारा बनाए गए नियम ही उनकी शक्तियों और कार्यों के दायरे के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को भी परिभाषित करते हैं। वैधानिक निगम वित्तीय रूप से स्वतंत्र संस्थाएँ हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों या प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखती हैं।

(iii) सरकारी कंपनियाँ:

सरकारी कंपनियाँ वे कंपनियाँ हैं जिनमें कम से कम 51 प्रतिशत पूंजी केंद्र या राज्य सरकार या दोनों के पास मिलाकर हो सकती है। कुछ मामलों में, आंशिक सरकारी स्वामित्व भी संभव है। सरकारी कंपनियाँ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकती हैं, कुछ हद तक निजी स्वामित्व को शामिल करते हुए सरकारी भागीदारी के अवसर प्रदान करती हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है:

सार्वजनिक क्षेत्र की ऐतिहासिक भूमिका:

भारत की स्वतंत्रता के समय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रमुख आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना गया था और उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे व्यवसायों में सीधे भाग लेकर या आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके योगदान देंगे।

आर्थिक नीतियों में परिवर्तन:

1990 के दशक के बाद के युग में, भारत नई आर्थिक नीतियों द्वारा चिह्नित एक परिवर्तन से गुजरा, जिसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया। इस बदलाव के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को फिर से परिभाषित किया गया। इसका उद्देश्य अब निष्क्रिय भूमिका निभाना नहीं था, बल्कि एक ही उद्योग के भीतर निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ बाजार में सक्रिय रूप से भाग लेने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

बुनियादी ढांचे का विकास:

औद्योगीकरण को समर्थन देने के लिए परिवहन संचार सुविधाओं, ईंधन, स्रोतों और बुनियादी एवं भारी उद्योगों जैसे महत्वपूर्ण ढांचे के विकास में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पर्याप्त पूंजी जुटाने, औद्योगिक निर्माण का समन्वय करने और तकनीशियनों और कार्यबल को प्रशिक्षण प्रदान करने की सरकार की अद्वितीय क्षमता ने इसे इस संदर्भ में उसे एक आवश्यक खिलाड़ी बना दिया है।

क्षेत्रीय संतुलन:

नियोजित विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्यों और क्षेत्रों के बीच असमानताओं को कम करके क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना था। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार को पहले से विकसित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की अत्यधिक वृद्धि को रोकते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने थे।

लागत-लाभ की अर्थव्यवस्थाएं:

भारत की स्वतंत्रता के बाद बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता

थी और ऐसे उद्योग आर्थिक विकास और वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण थे।

आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक :

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने निजी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण के प्रतिसंतुलन के रूप में कार्य किया। निजी क्षेत्र में, केवल कुछ औद्योगिक समूह भारी उद्योगों में निवेश करने के इच्छुक थे, जिससे धन संकेंद्रण हुआ और एकाधिकारवादी प्रथाओं को प्रोत्साहन मिला।

आयात प्रतिस्थापन:

दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, भारत का लक्ष्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ, विशेष रूप से भारी इंजीनियरिंग में शामिल कंपनियों की स्थापना आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

हाल के वर्षों में, सरकारी नीतियों ने सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं:

1991 से सरकारी नीति में परिवर्तन:

1991 से, सरकार ने संभावित रूप से योग्य एवं कार्य करनेवाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के पुनर्गठन और पुनर्जीवित करने के लिए नीतियाँ अपनाई हैं। जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था, वे बंद होने के अधीन हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक कुशल संसाधन आवंटन होता है।

व्यापक सार्वजनिक स्वामित्व और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी को 26 प्रतिशत या उससे कम करने का लक्ष्य रखा, जबकि अभी भी श्रमिकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 8 और बाद में 3 कर दी गई, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अधिकांश क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति मिल गई।

विनिवेश नीतियाँ पेश की गईं, जिससे निजी क्षेत्र और जनता दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र के समता अंशों की बिक्री संभव हो गई। यह रणनीति औद्योगिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कम करने के सरकार के निर्णय के अनुरूप थी।

बीमार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को उसी नीति के अधीन किया गया जो उनके निजी क्षेत्र के इकाइयों पर लागू होती है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यह निर्धारित करता है कि ऐसी इकाइयों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या बंद कर दिया जाना चाहिए।

प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली के तहत, पीएसयू प्रबंधनों को एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए जवाबदेह ठहराते हुए अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक उद्यमों, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी पर्याप्त पूंजी, विदेशी सहयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पाद

नवाचार, विपणन रणनीतियाँ और केंद्रीकृत नियंत्रण के साथ भारत के आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई व्यवसायों से संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करने वाले संयुक्त उद्यम भी भारत के कारोबारी माहौल के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरे।

विकास परियोजनाओं के कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रमुखता मिली।

इन नीतिगत परिवर्तनों ने सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं, इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया है, सरकारी इक्विटी को कम किया है और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, वैश्विक उद्यमों, संयुक्त उद्यमों और पीपीपी की भूमिकाएं भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए केंद्रीय बन गई हैं।

Things to remember:

The Indian economy encompasses a diverse range of business organizations, including small and large, industrial and trading, privately owned, and government-owned entities. This economic landscape is divided into two primary sectors: the private sector and the public sector.

Private Sector:

The private sector is composed of businesses owned by individuals or groups. Various organizational structures can be found within the private sector, including sole proprietorships, partnerships, joint Hindu family businesses, cooperatives, and companies. These businesses operate independently of direct government ownership or control.

Public Sector:

In contrast, the public sector consists of organizations that are owned and managed by the government. Public sector entities can be either wholly or partially owned by the central or state government.

Forms of Organizing Public Sector Enterprises:

As the government participates in various economic sectors, it necessitates specific organizational frameworks to manage its diverse enterprises. Public sector organizations can take on different forms, depending on the nature of their operations and their relationship with the government. There are three primary forms of public sector organization:

(i) Departmental Undertakings:

Departmental undertakings are established as integral departments of the ministry. These enterprises function as an extension of the government and operate under the direct purview of the ministry.

(ii) Statutory Corporations:

Statutory corporations are public enterprises created through special acts of Parliament. These acts define the scope of their powers and functions, as well as the rules and regulations governing their employees. Statutory corporations are financially independent entities that exercise control over specific areas or types of commercial activities.

(iii) Government Companies:

Government companies are firms in which at least 51 percent of the capital is held by the central or state government. In some cases, partial government ownership is also possible. Government companies may operate in various sectors, providing opportunities for government participation while incorporating private ownership to a certain extent.

The role of the public sector in India's economy has evolved significantly over the years:

Historical Role of Public Sector:

Initially, at the time of India's Independence, public sector enterprises were envisioned to play a pivotal role in achieving key economic objectives. They were expected to contribute either by directly participating in businesses or by acting as catalysts for economic development.

Transition in Economic Policies:

In the post-1990s era, India underwent a transition marked by new economic policies that emphasized liberalization, privatization, and globalization. This shift led to a redefinition of the public sector's role. It was no longer meant to play a passive role but was encouraged to actively participate and compete in the market alongside private sector companies within the same industry.

Development of Infrastructure:

The government's role in developing infrastructure, such as transportation and communication facilities, fuel and energy sources, and basic and heavy industries, was crucial for supporting industrialization. The government's unique capacity to mobilize substantial capital, coordinate industrial

construction, and provide training to technicians and the workforce made it an essential player in this context.

Regional Balance:

One of the significant objectives of planned development was to ensure regional balance by reducing disparities among states and regions. To achieve this, the government had to establish new enterprises in economically backward areas while preventing the excessive growth of the private sector in already developed regions.

Economies of Scale:

The public sector's involvement was particularly important in the establishment of large-scale industries, which required substantial capital investments to leverage economies of scale. Such industries are critical for economic development and growth.

Check on Concentration of Economic Power:

Public sector enterprises acted as a counterbalance to the concentration of economic power in the private sector. In the private sector, only a few industrial conglomerates were willing to invest in heavy industries, leading to wealth concentration and the encouragement of monopolistic practices.

Import Substitution:

During the second and third Five-Year Plan periods, India aimed to achieve self-reliance in various economic spheres. Public sector companies, particularly those involved in heavy engineering, were established to promote import substitution.

In more recent years, government policies have brought about significant changes in the public sector:

Government Policy Changes Since 1991:

Since 1991, the government has adopted policies to restructure and revive potentially viable Public Sector Undertakings (PSUs). Those who cannot be revived are subject to closure, resulting in more efficient resource allocation.

To promote broader public ownership and participation, the government aimed to reduce its equity stake in non-strategic PSUs to 26 percent or lower, while still fully protecting the interests of workers.

The number of industries reserved for the public sector was reduced from 17 to 8, and subsequently to 3, allowing private sector

entry into most sectors to foster competition.

Disinvestment policies were introduced, enabling the sale of PSU equity shares to both the private sector and the public. This strategy aligned with the government's decision to reduce its presence in the industrial sector.

Sick public sector units were subjected to a policy similar to that applied to their private sector counterparts. The Board of Industrial and Financial Reconstruction determined whether such units should be restructured or closed.

A Memorandum of Understanding (MoU) system was implemented to enhance performance. Under this system, PSU managements were granted greater autonomy while being held accountable for achieving specified results.

The role of global enterprises, specifically Multinational Corporations (MNCs), became increasingly significant in the Indian economy. MNCs, with their substantial capital, foreign collaborations, advanced technology, product innovation, marketing strategies, and centralized control, played a pivotal role in India's economic landscape.

Joint ventures, involving the pooling of resources and expertise from multiple businesses to achieve specific goals, also emerged as an important aspect of India's business environment.

Public-Private Partnerships (PPPs) gained prominence as a collaborative approach between the public and private sectors for efficient allocation and execution of development projects.

These policy changes have brought about significant transformations in the public sector, making it more competitive, reducing government equity, and promoting private sector participation. Moreover, the roles of global enterprises, joint ventures, and PPPs have become central to India's economic growth and development.

बहुवैकल्पिक प्रश्न (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

1. सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी कौन होता है।

- (a) निजीव्यक्ति (b) आम जनता
(c) सरकार (d) उपरोक्त कोई नहीं

Who is the owner of a public enterprise?

- (a) Private individual. (b) General public.

- (c) Government (d) None of the above

2. सार्वजनिक उपक्रमों की उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है।

- (a) सांसद/ जनता (b) पुलिस
(c) न्यायपालिका (d) उपरोक्त कोई नहीं

To whom are public enterprises accountable?

- (a) Parliamentary/Public
(b) Police
(c) Judiciary
(d) None of the above

3. सार्वजनिक उपक्रमों को आवश्यक पूंजी कहाँ से प्राप्त होती है।

- (a) विदेश से.
(b) बैंकों से
(c) निजी व्यक्ति से
(d) सरकार द्वारा बजट प्रावधान से

From where do public enterprises get the necessary capital?

- (a) From abroad.
(b) From banks.
(c) From private individuals
(d) From budget provision by the government

4. सार्वजनिक उपक्रम का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है।

- (a) औद्योगीकरण को बढ़ावा
(b) आर्थिक विषमता लाना.
(c) रोजगार में कमी
(d) एकाधिकार प्रवृत्ति लाना

What is the social responsibility of a public enterprise?

- (a) Promotion of industrialization.
(b) Bringing economic inequality.
(c) Reduction in employment.
(d) Bringing monopoly tendency

5. लाल फीता शाही किस प्रकार के उपक्रमों में पाई जाती है

- (a) निजी उपक्रम (b) सहकारी उपक्रम
(c) विदेशी उपक्रम (d) सार्वजनिक उपक्रम

Red tapism is found in which types of undertakings?

- (a) Private Enterprise.
(b) Cooperative Enterprise
(c) Foreign Enterprise
(d) Public Enterprise

6. निजी उपक्रम की स्थापना में पूंजी किसके द्वारा लगाई जाती है

- (a) सरकार के द्वारा

- (b) साहसी निजी व्यक्ति द्वारा
(c) बैंक द्वारा
(d) आम जनता द्वारा
- Who invests capital in setting up a private enterprise?**
(a) By the government
(b) By a courageous private individual
(c) By the bank
(d) By the general public
7. **निजी उपक्रम किस प्रेरणा पर कार्य करते हैं**
(a) लाभ की प्रेरणा
(b) रोजगार वृद्धि की प्रेरणा
(c) समाज सेवा की प्रेरणा.
(d) उपरोक्त कोई नहीं
- On what motivation do private enterprises work?**
(a) Motivation of profit
(b) Motivation of employment growth
(c) Motivation of social service
(d) None of the above
8. **"उपभोक्ता ही सर्वोपरि है" किस क्षेत्र का नारा है**
(a) सार्वजनिक क्षेत्र (b) सहकारी क्षेत्र
(c) निजी क्षेत्र (d) उपरोक्त सभी
- "Consumer is supreme" is the slogan of which sector?**
(a) Public sector
(b) Co-operative sector.
(c) Private sector.
(d) All of the above
9. **शीघ्र निर्णय किस क्षेत्र की विशेषता है**
(a) निजी उपक्रम (b) संयुक्त उपक्रम
(c) सार्वजनिक उपक्रम (d) उपरोक्त सभी
- Which field is characterized by quick decisions?**
(a) Private undertaking (b) Joint undertaking
(c) Public undertaking (d) All of the above
10. **आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण को कौन प्रोत्साहित करता है**
(a) संयुक्त उपक्रम (b) सार्वजनिक उपक्रम
(c) निजी उपक्रम (d) सरकारी उपक्रम
- What encourages centralization of economic power?**
(a) Joint venture.
(b) Public undertaking
(c) Private undertaking
(d) Government undertaking
11. **आर्थिक विषमता को कौन क्षेत्र बढ़ाता है**
(a) निजी क्षेत्र (b) सार्वजनिक क्षेत्र
(c) सरकारी क्षेत्र (d) सहकारी संगठन
- Which sector increases economic inequality?**
(a) Private Sector
(b) Public Sector
(c) Government Sector
(d) Cooperative Organization
12. **सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बीच हुई साझेदारी को क्या कहा जाता है**
(a) निजी क्षेत्र (b) मिश्रित क्षेत्र
(c) सार्वजनिक क्षेत्र (d) सहकारी क्षेत्र
- What is the partnership between public sector and private sector called?**
(a) Private sector (b) Mixed sector
(c) Public sector (d) Cooperative sector
13. **निजी क्षेत्र के संबंध में कानून कौन बनाता है**
(a) सरकार (b) सार्वजनिक क्षेत्र
(c) स्वयं निजी क्षेत्र (d) न्यायालय
- Who makes laws regarding private sector**
(a) Government
(b) Public sector
(c) Private sector itself.
(d) Court
14. **शोषण की प्रवृत्ति/ मनोवृत्ति किस प्रकार की उपक्रम में पाई जाती है**
(a) निजी क्षेत्र (b) सहकारी क्षेत्र
(c) सार्वजनिक क्षेत्र (d) मिश्रित क्षेत्र
- In which type of enterprise is the tendency of exploitation found?**
(a) Private sector. (b) Cooperative sector
(c) Public sector (d) Mixed sector
15. **लोच शीलता किस प्रकार के उपक्रमों में ज्यादा पाई जाती है**
(a) सार्वजनिक क्षेत्र (b) मिश्रित क्षेत्र
(c) निजी क्षेत्र (d) उपरोक्त कोई नहीं
- Flexibility is found more in which type of enterprises?**
(a) Public sector (b) Mixed sector
(c) Private sector (d) None of the above
16. **कार्य करने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता किस उपक्रम में ज्यादा होती है**
(a) मिश्रित क्षेत्र (b) सार्वजनिक क्षेत्र
(c) निजी क्षेत्र (d) उपरोक्त सभी
- In which enterprise is there more freedom to work and take decisions?**

- (a) Mixed sector (b) Public sector
(c) Private sector (d) All of the above
17. गोपनीयता का तत्व कहाँ ज्यादा पाया जाता है
(a) सहकारी क्षेत्र (b) मिश्रित क्षेत्र
(c) सार्वजनिक क्षेत्र (d) निजी क्षेत्र
- Where is the element of privacy found more?**
(a) Co-operative sector
(b) Mixed sector
(c) Public sector
(d) Private sector
18. सरकारी अंकेक्षण करना कहाँ अनिवार्य है
(a) निजी क्षेत्र (b) सहकारी क्षेत्र
(c) सार्वजनिक क्षेत्र (d) उपरोक्त कोई नहीं
- Where is it mandatory to conduct government audit?**
(a) Private Sector
(b) Cooperative Sector
(c) Public Sector
(d) None of the above
19. परिचालन में स्वतंत्रता कहाँ ज्यादा पाई जाती है
(a) निजी क्षेत्र (b) सार्वजनिक क्षेत्र
(c) मिश्रित क्षेत्र (d) उपरोक्त सभी
- Where is freedom in operation more?**
(a) Private sector (b) Public sector
(c) Mixed sector (d) All of the above
20. पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति कहाँ की जाती है
(a) सरकारी उपक्रम में (b) सहकारी उपक्रम में
(c) निजी उपक्रम में (d) इनमें से कोई नहीं
- Where are professional managers appointed?**
(a) In government undertaking
(b) In co-operative undertaking
(c) In private undertaking
(d) None of these
21. भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम
(a) आवश्यक है (b) अनावश्यक है
(c) भार है (d) कह नहीं सकते
- Government Undertakings for India's Economy**
(a) is necessary (b) is unnecessary
(c) is a burden (d) can't say
22. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की पुनर्रचना किसके द्वारा की जाती है
(a) एम ओ एफ ए (b) एम ओ यू
(c) बी आई एफ आर (d) एन आर एफ
- Restructuring of sick public sector units is done by**
(a) M O F A (b) M O U
(c) B I F R (d) N R F
23. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश का अर्थ है
(a) सार्वजनिक क्षेत्र के समता अंशों की बिक्री
(b) परिचालन को बंद करना
(c) नए क्षेत्रों में निवेश
(d) सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना
- Disinvestment in public sector units means**
(a) Sale of equity shares in the public sector.
(b) Discontinuation of operations.
(c) Investment in new sectors.
(d) Capital infusion into the public sector.
24. विभागीय उपक्रम के कार्यकलाप की रिपोर्ट वर्ष के अंत में कहाँ प्रस्तुत की जाती है
(a) संसद/ विधानसभा में (b) राज्यपाल को
(c) प्रधानमंत्री को (d) न्यायालय में
- Where is the report of the activities of the departmental undertaking presented at the end of the year?**
(a) In Parliament/Assembly
(b) To the Governor
(c) To the Prime Minister
(d) In the court
25. विभागीय उपक्रम के सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है
(a) संबंधित मंत्री (b) सीएजी
(c) न्यायालय (d) उपरोक्त सभी
- Who is the highest officer of a departmental undertaking?**
(a) Minister concerned
(b) CAG
(c) Court
(d) All of the above
26. विभागीय उपक्रम का उदाहरण है
(a) बाटा (b) रिलायंस
(c) टाटा (d) भारतीय रेलवे
- An example of a departmental undertaking is**
(a) Bata (b) Reliance
(c) Tata (d) Indian Railways
27. विभागीय उपक्रम के कर्मचारी क्या कहलाते हैं
(a) सरकारी कर्मचारी (b) अस्थाई कर्मचारी
(c) निजी कर्मचारी (d) अनुबंध कर्मचारी
- What are the employees of departmental**

undertaking called?

- (a) Government employee
- (b) Temporary employee
- (c) Private employee
- (d) Contract employee

28. विभागीय उपक्रम की समस्त आय कहां जमा होती है

- (a) ट्रेजरी में
- (b) प्रबंधकों के खाते में
- (c) निजी बैंकों में
- (d) कहीं नहीं

Where is the entire income of the departmental undertaking deposited?

- (a) In treasury
- (b) In managers' account
- (c) In private banks
- (d) Nowhere

29. विभागीय उपक्रम की स्थापना कहां उचित मानी जाती है

- (a) आधारभूत उद्योगों में
- (b) निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले उद्योगों में
- (c) लाभ कमाने वाले उद्योगों में
- (d) उपरोक्त कोई नहीं

Where is it considered appropriate to establish a departmental undertaking?

- (a) in basic industries
- (b) in industries promoting exports
- (c) in profit making industries
- (d) none of the above

30. ऐसी सरकारी संस्था जिसकी स्थापना सांसद के विशेष अधिनियम द्वारा होती है क्या कहलाती है

- (a) वैधानिक निगम
- (b) निजी कंपनी
- (c) सरकारी कंपनी
- (d) उपरोक्त सभी

What is a government institution established by a special Act of the Parliament called?

- (a) Statutory corporation
- (b) Private company
- (c) Government company
- (d) All of the above

31. वैधानिक निगम का उदाहरण है

- (a) जीवन बीमा निगम
- (b) रिलायंस कंपनी
- (c) अमेज़ॉन
- (d) टाटा कंपनी

Example of statutory corporation is

- (a) Life Insurance Corporation
- (b) Reliance Company
- (c) Amazon
- (d) Tata Company

32. वैधानिक अथवा लोक निगम की समस्त पूंजी किसके द्वारा लगाई जाती है

- (a) सरकार द्वारा
- (b) बैंकों द्वारा
- (c) निजी क्षेत्र द्वारा
- (d) आम जनता द्वारा

By whom is the entire capital of a statutory or public corporation invested?

- (a) By the government
- (b) By the banks
- (c) By the private sector
- (d) By the general public

33. वैसी कंपनी जिसकी कुल पूंजी का कम से कम 51% भाग सरकार द्वारा लगाई जाए कहलाती है

- (a) सहकारी कंपनी
- (b) मिश्रित कंपनी
- (c) सरकारी कंपनी
- (d) निजी कंपनी

A company in which at least 51% of its total capital is invested by the government is called

- (a) Co-operative company
- (b) Mixed company
- (c) Government company
- (d) Private company

34. सरकारी कंपनी की स्थापना कैसे होती है

- (a) सरकार द्वारा
- (b) संसद द्वारा
- (c) कंपनी कानून 1956 से
- (d) उपरोक्त सभी प्रकार से

How is a government company established?

- (a) By the government
- (b) By the Parliament.
- (c) Company Act 1956
- (d) All the above

35. जब किसी राजकीय उपक्रम का प्रबंध तथा नियंत्रण निजी बोर्ड द्वारा किया जाता है तो वह कहलाता है

- (a) बोर्ड द्वारा प्रबंधित उपक्रम
- (b) सार्वजनिक उपक्रम
- (c) सरकारी कंपनी
- (d) निजी कंपनी

When a government undertaking is managed and controlled by a private board, it is called

- (a) Board managed through undertaking
- (b) Public undertaking
- (c) Government company
- (d) Private company

36. सरकार की नई औद्योगिक नीति में किस क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है

- (a) विभागीय उपक्रम
- (b) सरकारी कंपनी

- (c) वैधानिक निगम (d) निजी उपक्रम

Which sector is being given more emphasis in the new industrial policy of the government?

- (a) Departmental undertaking
(b) Government company
(c) Statutory corporation
(d) Private undertaking

37. औद्योगिक वित्त निगम उदाहरण है

- (a) सार्वजनिक निगम (b) सरकारी कंपनी
(c) विभागीय उपक्रम (d) इनमें से कोई नहीं

Industrial Finance Corporation is example of

- (a) Public corporation
(b) Government company.
(c) Departmental Undertaking
(d) None of these

38. विभागीय उपक्रम में होती है

- (a) सेवा भावना (b) गोपनीयता
(c) मितव्ययिता (d) ये सभी

Occurs in departmental undertaking

- (a) spirit of service (b) confidentiality
(c) frugality (d) all of these

39. वैधानिक निगम के प्रमुख लक्षण हैं

- (a) सरकार का पूर्ण नियंत्रण
(b) पृथक् वैधानिक अस्तित्व
(c) संसद के प्रति जवाबदेही
(d) ये सभी

The main characteristics of a statutory corporation are

- (a) Complete control of the government
(b) Separate legal existence
(c) Accountability to Parliament
(d) All of these

40. यदि कोई उपक्रम अपने नाम से व्यापार विश्व के अनेक देशों में करती है तो वह कहलाती है

- (a) भूमंडलीय उपक्रम (b) वैधानिक उपक्रम
(c) सरकारी कंपनी (d) उपरोक्त कोई नहीं

If an enterprise does business under its own name in many countries of the world, then it is called

- (a) Global enterprise.
(b) Statutory undertaking.
(c) Government Company
(d) None of the above

41. कोका कोला किस प्रकार की कंपनी है

- (a) बहुराष्ट्रीय कंपनी (b) स्थानीय कंपनी

- (c) सरकारी कंपनी (d) उपरोक्त कोई नहीं

What type of company is Coca Cola?

- (a) Multinational company
(b) Local company
(c) Government company
(d) None of the above

42. बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कितने देश में होता है

- (a) एक (b) दो
(c) तीन (d) कई देशों में

In how many countries are multinational companies registered?

- (a) one (b) two
(c) three (d) in many countries

43. बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है

- (a) लाभ कमाना (b) समाज सेवा
(c) रोजगार सृजन (d) देश की आर्थिक वृद्धि

What is the main objective of multinational companies?

- (a) Making profit
(b) Social service
(c) Employment creation
(d) Economic growth of the country

44. बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस वर्ग के लोगों के लिए उत्पाद बनाती हैं

- (a) मध्य वर्ग (b) उच्च वर्ग
(c) निम्न वर्ग (d) सभी वर्गों के लिए

For which class of people do multinational companies make products?

- (a) Middle class (b) Upper class
(c) Lower class (d) For all classes

45. भारत में किस वर्ष के पश्चात से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवसाय बढ़ा है

- (a) 1990 (b) 1991
(c) 1992 (d) 1993

In which year the business of multinational companies is increased in India?

- (a) 1990 (b) 1991
(c) 1992 (d) 1993

46. जब कोई कम्पनी अंतराष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों के उपक्रम के साथ मिलकर व्यवसाय शुरू करती है तो वह कहलाती है

- (a) बहुराष्ट्रीय कंपनी
(b) सार्वजनिक निजी भागीदारी
(c) संयुक्त उपक्रम

(d) उपरोक्त सभी

When a company starts business in the international market in collaboration with enterprises of other countries, it is called

- (a) Multinational company
- (b) Public private partnership
- (c) Joint venture
- (d) All of the above

47. संयुक्त उपक्रम से क्या लाभ होता है

- (a) विदेशी बाजार में आसान प्रवेश.
- (b) नई तकनीक का लाभ
- (c) जोखिम में कमी.
- (d) उपरोक्त सभी

What are the benefits of joint venture ?

- (a) Easy entry into foreign market.
- (b) Benefits of new technology.
- (c) Reduction in risk.
- (d) All of the above

48. जब सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र साथ मिलकर सार्वजनिक सेवाएं आम जनता को देती हैं तो उसे क्या कहा जाता है

- (a) सार्वजनिक निजी साझेदारी
- (b) भूमंडलीय उपक्रम
- (c) संयुक्त उपक्रम
- (d) उपरोक्त कोई नहीं

What is it called when the public sector and private sector together provide public services to the general public?

- (a) Public Private Partnership
- (b) Global Venture
- (c) Joint Venture
- (d) None of the above

49. बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र होता है

- (a) स्थानीय
- (b) राष्ट्रीय
- (c) अंतरराष्ट्रीय
- (d) इनमें से कोई नहीं

The area of a multinational company is

- (a) Local
- (b) National
- (c) International.
- (d) none of these

50. भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ

- (a) उत्पादन में वृद्धि.
- (b) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि
- (c) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि
- (d) उपरोक्त सभी

What was the impact of globalization of business in India?

- (a) an increase in production.

(b) increase in international trade

(c) Increase in foreign direct investment

(d) All of the above

51. भारत में उदारीकरण का क्या प्रभाव हुआ

- (a) विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि
- (b) निर्यात में वृद्धि
- (c) विकास की दर में वृद्धि
- (d) उपरोक्त सभी

What was the effect of liberalization in India?

- (a) Increase in foreign exchange reserves
- (b) Increase in exports
- (c) Increase in the rate of growth
- (d) All of the above

52. बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीय कृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है

- (a) शाखाएं
- (b) संसद
- (c) मुख्यालय
- (d) सहायक कंपनी द्वारा

Who is the centralized control authority in a multinational company?

- (a) Branches
- (b) Parliament
- (c) Headquarters
- (d) Subsidiary Company

53. भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व

- (a) कम हो रहा है
- (b) बढ़ रहा है
- (c) कोई परिवर्तन नहीं
- (d) उपरोक्त कोई नहीं

Importance of MNCs in India

- (a) is decreasing.
- (b) is increasing.
- (c) No change.
- (d) none of the above

54. सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक दूसरे के

- (a) विपरीत है
- (b) पूरक है
- (c) विरोधी है
- (d) उपरोक्त सभी

Public sector and private sector to each other

- (a) is opposite
- (b) is complementary
- (c) is contradictory
- (d) all of the above

55. भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनाई गई

- (a) 1947
- (b) 1948
- (c) 1956
- (d) 1991

When was India's first industrial policy made?

- (a) 1947
- (b) 1948
- (c) 1956
- (d) 1991

56. भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है

- (a) मिश्रित
- (b) समाजवादी

- (c) पूंजीवादी (d) उपरोक्त सभी

What type of economy is India

- (a) Mixed (b) Socialist
(c) Capitalist (d) All of the above

57. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

What is the number of industries reserved for the public sector?

- (a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

58. निजी उद्योगों की सफलता कैसे मापी जाती है

- (a) रोजगार प्रदान करने से
(b) लाभ की मात्रा से
(c) कर देने से
(d) उपरोक्त सभी

How is the success of private industries measured?

- (a) By providing employment
(b) By the amount of profit
(c) By paying tax
(d) All of the above

59. संसदीय समितियां किस उद्योग के कार्यों की छानबीन कर सकती हैं

- (a) लोक उद्योग (b) निजी उद्योग
(c) सहकारी उद्योग (d) उपरोक्त सभी

Parliamentary committees can scrutinize the actions of which industry?

- (a) Public Industry
(b) Private Industry
(c) Cooperative Industry
(d) All of the above

60. लोक उपक्रमों के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है

- (a) अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व
(b) अपने ग्राहकों की प्रति उत्तरदायित्व
(c) अपने समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व
(d) उपरोक्त सभी

Meaning of Social Responsibility of Public Undertakings

- (a) Responsibility to our owners
(b) Responsibility to our customers
(c) Responsibility to our community
(d) All of the above

61. उद्योगों की राष्ट्रीयकरण का अर्थ है

- (a) निजी उद्योगों को सरकार द्वारा नियंत्रण में लेना
(b) सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र को देना
(c) उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं
(d) उपरोक्त दोनों

Nationalization of industries means

- (a) Taking control of private industries by the government
(b) Giving public industries to the private sector
(c) None of the above
(d) Both of the above

62. राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य है

- (a) लाभ बढ़ाना
(b) कर ज्यादा देना
(c) लाभ की जगह जन सेवा को प्राथमिकता
(d) प्रबंधन की कुशलता बढ़ाना

The main objective of nationalization is

- (a) Increasing profits
(b) Paying more taxes
(c) Prioritizing public service over profit.
(d) Increasing efficiency of management

63. जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया

- (a) 1957 (b) 1958
(c) 1959 (d) 1960

When was the life insurance business nationalized?

- (a) 1957 (b) 1958
(c) 1959 (d) 1960

64. संयुक्त क्षेत्र की स्थापना का क्या उद्देश्य था

- (a) सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन
(b) निजी क्षेत्र के एकाधिकार को रोकना
(c) निजी क्षेत्र में समाजवादी भावना बढ़ाना
(d) उपरोक्त सभी

What was the purpose of establishing the Joint Venture?

- (a) Poor performance of the public sector
(b) Restriction of a right of the private sector
(c) Increasing socialist sentiment in the private sector.
(d) All of the above

65. डाक एवं तार सेवा किस प्रकार के लोक उद्यम है

- (a) विभागीय उपक्रम (b) सार्वजनिक उपक्रम
(c) सरकारी कंपनी (d) सूत्रधारी कंपनी

What type of public enterprises are Postal and Telegraph Services?

- (a) Departmental Undertaking

- (b) Public Undertaking
- (c) Government Company.
- (d) holding company

66. भारत में किस प्रकार का प्रारूप तेजी से विकसित हो रहा है

- (a) सार्वजनिक क्षेत्र (b) सरकारी कंपनी
- (c) संयुक्त उपक्रम (d) निजी क्षेत्र

Which type of format is developing rapidly in India

- (a) Public Sector.
- (b) Government company
- (c) Joint venture
- (d) Private sector

67. किस प्रकार के उद्यम को स्थापित करने में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है

- (a) सरकारी कंपनी (b) बहुराष्ट्रीय कंपनी
- (c) निजी कंपनी (d) संयुक्त उपक्रम

Which type of enterprise requires a lot of capital to set up?

- (a) Government company
- (b) Multinational company.
- (c) Private company.
- (d) joint venture

68. बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश किस मुद्रा में करती है

- (a) रुपया में (b) डॉलर में
- (c) दोनों में (d) स्वर्ण में

In which currency does the multinational company invest?

- (a) In Rupees. (b) in dollars.
- (c) in both (d) in gold

69. बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से

- (a) छोटे और स्थानीय उद्योग बढ़े हैं
- (b) छोटे और स्थानीय उद्योग घटे हैं
- (c) कोई असर नहीं पड़ा है
- (d) उपरोक्त सभी

With the arrival of the multinational company

- (a) Small and local industries have increased
- (b) Small and local industries have decreased.
- (c) Has no effect
- (d) All of the above

70. सोनी कंपनी किस प्रकार की कंपनी है

- (a) सरकारी कंपनी
- (b) संयुक्त उपक्रम
- (c) बहुराष्ट्रीय कंपनी
- (d) सार्वजनिक कंपनी

What type of enterprise is Sony Company?

- (a) Government company
- (b) Joint venture
- (c) Multinational company.
- (d) public company

बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर (M C Q ANSWERS)

1	C	2	A	3	D	4	A	5	D
6	B	7	A	8	C	9	A	10	C
11	A	12	B	13	A	14	A	15	C
16	C	17	D	18	B	19	A	20	C
21	A	22	C	23	A	24	A	25	A
26	D	27	A	28	A	29	A	30	A
31	A	32	A	33	C	34	C	35	A
36	D	37	A	38	D	39	D	40	A
41	A	42	A	43	A	44	B	45	B
46	C	47	D	48	A	49	C	50	D
51	D	52	C	53	B	54	B	55	B
56	A	57	B	58	B	59	A	60	D
61	A	62	C	63	C	64	D	65	A
66	D	67	B	68	B	69	B	70	C

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Questions)

1. सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं।

उत्तर: सार्वजनिक क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन संस्थाओं से होता है जो जनसाधारण को सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित तथा प्रबंधित की जाती हैं।

What do you understand by public sector?

Ans: By public sector we mean those institutions which are owned, controlled and managed by the government to provide services to the general public.

2. निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं।

उत्तर: निजी क्षेत्र की संस्थाएं वह होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई, नियंत्रित एवं प्रबंधित की जाती हैं।

What do you understand by private sector?

Ans: Private sector organizations are those which are run, controlled and managed by private individuals for the purpose of earning profit.

3. सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों की कहां जवाबदेही होती है।

उत्तर: सार्वजनिक क्षेत्र की जबाबदेही लोकसभा के माध्यम से आम जनता के प्रति होती है और निजी क्षेत्र के उपक्रम अपने निवेशकों के प्रति जवाबदेह होते हैं।

Where does the accountability of public

sector and private sector enterprises lie?

Ans: The public sector is accountable to the general public through the Lok Sabha and the private sector enterprises are accountable to their investors.

4. सार्वजनिक उपक्रम के कितने प्रकार होते हैं।

उत्तर: सार्वजनिक उपक्रम के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं

- 1 विभागीय संगठन
- 2 लोक निगम
- 3 सरकारी कंपनी

How many types of public enterprises are there?

There are mainly three types of public enterprises

- 1 Departmental organization
- 2 Public Corporation
- 3 Government company

5. विभागीय संगठन से आप क्या समझते हैं।

उत्तर: विभागीय संगठन सार्वजनिक उपक्रम का एक प्रारूप है जिसका नियंत्रण सरकार के एक मंत्रालय द्वारा किया जाता है और संबंधित मंत्रालय का मंत्री उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है।

What do you understand by departmental organization?

Departmental organization is a form of public enterprise which is controlled by a ministry of the government.

6. वैधानिक / लोक निगम कौन कहलाता है।

उत्तर: यदि किसी उपक्रम की स्थापना संसद या प्रादेशिक विधानसभाओं के विशेष अधिनियम द्वारा होती है तो वह लोक निगम कहलाती है, जैसे एल.आई.सी.।

What is a statutory/public corporation?

If any undertaking is established by a special act of the Parliament or regional assemblies, then it is called a public corporation, like L.I.C.

7. सरकारी कंपनी किसे कहते हैं।

उत्तर: जब किसी कंपनी की स्थापना कंपनी कानून के तहत हो और उसकी कुल पूंजी का कम से कम 51% सरकार द्वारा लगाया गया हो तो उसे सरकारी कंपनी कहते हैं।

what do you understand by government company.

Ans: When a company is established under the Company Law and at least 51% of its total capital is invested by the government, then it is called a government company

8. बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन होती होती हैं।

उत्तर: दो या दो से अधिक देश में व्यवसाय एवं प्रबंध करने

वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं।

What are multinational companies?

Ans: Companies doing business and management in two or more countries are called multinational companies.

9. सरकारी कंपनी के अंश किसके नाम से खरीदे जाते हैं।

उत्तर: सरकारी कंपनी के अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम से खरीदे जाते हैं।

In whose name are the shares of a government company purchased?

Ans: Shares of a government company are purchased in the name of the President of India.

10. सार्वजनिक निजी साझेदारी क्या है।

उत्तर: जब निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है और वित्तीय, तकनीकी तथा परिचालन जोखिम को वहन करती है तब वह सार्वजनिक निजी साझेदारी कहलाती है।

What is public private partnership?

Ans: When the private sector collaborates with the public sector to provide public services and bear the financial, technical and operational risks, then it is called public private partnership.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख लक्षणों को बताएं।

उत्तर: सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख लक्षण हैं:-

- A सरकार के हाथ में उपक्रम का स्वामित्व होता है
- B स्थापना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सेवा प्रदान करना होता है
- C सरकारी स्रोतों से वित्तीय प्रावधान किया जाता है
- D प्रबंध में लाल फीता शाही एवं अफसरशाही हावी होती है
- E सांसद तथा जनता के प्रति जवाबदेही होती है

Explain the main characteristics of public enterprises.

Ans: The main characteristics of public enterprises are:-

- A The ownership of the enterprise is in the hands of the government.
- B The main objective of the establishment is to provide social services.
- C Financial provision is made from government sources.
- D Red tapism and bureaucracy dominate the management.

E There is accountability towards the Parliament and the public.

2. निजी क्षेत्र के गुण और देशों को बताएं।

उत्तर: गुण

A देश में प्रचलित कानून के अंदर कार्य करने की स्वतंत्रता होती है।

B निजी लाभ की प्रेरणा से काम करते हैं

C गोपनीयता के साथ शीघ्र निर्णय लिया जाता है

D दक्षता एवं कठिन परिश्रम की प्रेरणा पायी जाती है
दोष

A आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है

B सामाजिक हितों की अनदेखी होती है।

C दुर्लभ संसाधनों का दोहन ज्यादा होता है।

D सामाजिक उत्तरदायित्व पर ध्यान नहीं देते हैं

2 Explain the merits and demerits of the private sector.

Ans: Merits

A There is freedom to work within the laws prevalent in the country.

B Work with the motivation of personal gain

C Decisions are taken quickly with confidentiality

D Inspiration of efficiency and hard work is found

Demerits

A Economic power may be centralized

B Social interests may be ignored.

C Scarce resources are over-exploited

D Don't pay attention to social responsibility

3. निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है

उत्तर: निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं:-

1 स्थापना -

निजी क्षेत्र की स्थापना निजी व्यक्तियों द्वारा की जाती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना सरकार द्वारा की जाती है

2 उद्देश्य-

निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाना होता है।

3 प्रबंध -

निजी क्षेत्र का प्रबंध किसी निजी पेशेवर प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है इसकी विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों द्वारा होता है।

4 अंकेक्षण -

निजी क्षेत्र को सरकारी अंकेक्षण करवाना जरूरी नहीं है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को सरकारी अंकेक्षण करवाना जरूरी होता है।

What is the difference between the private sector and public sector?

Ans: The main differences between private sector and public sector are as follows:-

1 Establishment -

Private sector is established by private individuals while the public sector is established by the government.

2 Objective -

The main objective of the private sector is to earn profit, but the main objective of the public sector is to benefit the society.

3. Management -

Private sector is managed by private professional managers, on the contrary, public sector is managed by government employees.

4. Audit -

Private sector is not required to get government audit done whereas public sector is required to get government audit done.

4. भूमंडलीय या बहुराष्ट्रीय उपक्रम क्या लक्षण अथवा विशेषताएं हैं।

उत्तर: भूमंडलीय उपक्रम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं :-

1 इनका व्यवसाय एक से अधिक क्षेत्र में होता है

2 भूमंडलीय उपक्रम की स्थापना मूल रूप से किसी विशिष्ट देश में होती है जहां इनका मुख्यालय होता है।

3 इनमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है

4 बड़ी मात्रा में उत्पादन तथा वितरण का ये कार्य करते हैं

5 साथ ही भूमंडलीय उपक्रम विज्ञापन तथा विक्रय कला पर ज्यादा जोर देते हैं।

What are the characteristics or features of a global or multinational enterprise?

Ans: The main characteristics of global enterprises are as follows:-

1. Their business is done in more than one region.

2. Global enterprises are basically established in a specific country where they have their headquarters.

3 Modern technology is used in these enterprises

4 They do the work of production and distribution in large quantities.

5 At the same time, global enterprises place more emphasis on advertising and salesmanship.

5. संयुक्त उपक्रम स्थापित होने का क्या कारण है।

उत्तर: आजकल संयुक्त उपक्रम ज्यादा स्थापित होती जा रहे हैं, क्योंकि विदेशी उद्योगपति अपने स्थानीय साथी के साथ आसानी से देशी बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। सरकार भी निजी क्षेत्र की प्रबंध कुशलता को अब स्वीकार करने लगी है और उसका लाभ लेना चाहती हैं साथ ही निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों की भावना अब कुछ समाजवादी भी होने लगी है और वह मिलकर अब अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने को तैयार हो रहे हैं। इन सब कारणों के कारण ही आज संयुक्त उपक्रम ज्यादा स्थापित हो रहा है।

What is the reason for setting up a joint venture?

Ans: Nowadays, joint ventures are becoming more established, because foreign industrialists easily enter the domestic market with their local partners. The government has also started accepting the management efficiency of the private sector and wants to take advantage of it. The sentiments of the industrialists of the region have also started becoming somewhat socialist and they are getting ready to offer their services jointly. Due to all these reasons, more joint ventures are being established today.

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
(Long Answer Type Questions)

1. बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं भारत में इसकी कितनी उपयोगिता है?

उत्तर: कई देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियां को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। उनकी स्थापना किसी एक देश में की जाती है, और वहां ही उनका मुख्यालय होता है जहां से वे सारे विश्व में किए जाने वाले व्यापार को नियंत्रित तथा नियमित करते हैं। इनके पास विशाल आर्थिक साधन होते हैं तथा इनके उप कार्यालय तथा कारखाना अनेक देशों में खोले जाते हैं। अपने संपूर्ण विश्व में कुशल प्रबंधन को बनाए रखने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुशल दक्ष प्रशिक्षित एवं विशिष्ट योग्यता वाले पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति अपने यहां करते हैं। इनके माध्यम से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, देश को उच्च तकनीक और विदेशी पूंजी भी प्राप्त होती है तथा आम जनता को अनेक प्रकार की वस्तुओं में से कोई एक के चुनाव का अवसर प्राप्त होता है।

कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की

अनदेखी भी करके मात्र लाभ कमाने पर ज्यादा ध्यान देने लगी है, और साथ ही एकाधिकार के निर्माण का प्रयास करती है। यह देश के प्राकृतिक संसाधनों का अव्यवस्थित रूप से दोहन करती है और अपने देश की पुरानी तकनीक को ही दूसरे देशों में उपयोग करती है भारत में उपयोगिता -

बहुराष्ट्रीय कंपनियां से देश को होने वाले लाभ एवं हानियों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में इनकी स्थापना से लाभ हो सकता है यदि इनकी स्थापना कुछ शर्तों के साथ की जाए जैसे :-

1 लाभ का कुछ भाग ही ये अपने देश ले जाए और लाभ का कुछ भाग भारत में ही विनियोजित करने का प्रावधान करना चाहिए।

2 स्थानीय राजनीति में इनके हस्तक्षेप पर रोक होनी चाहिए।

3 प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इन्हें उचित शर्तों के साथ करने देनी चाहिए।

4 इन्हें गरीब लोगों के उपभोग की वस्तुएं भी तैयार की करना चाहिए।

5 इन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रेरित भी करनी चाहिए।

What do you understand about a multinational company? How useful is it in India?

Ans: Companies doing business in many countries are called multinational companies. They are established in one country and have their headquarters from where they control and regulate the business done all over the world. They have huge financial resources and their sub-offices and factories are opened in many countries. To maintain efficient management throughout their world, multinational companies appoint professional managers with skilled, trained and specialized qualifications.

Through these, employment opportunities increase in the country, the country also gets high technology and foreign capital and the general public gets the opportunity to choose among many types of goods.

Many multinational companies have started focusing more on making profits, ignoring national priorities, and at the same time trying to create monopolies. It exploits the country's natural resources in a haphazard manner and uses its country's old technology in other countries.

Utility in India -

After looking at the benefits and disadvantages of multinational companies to the country, we can say that their establishment in a developing country like India can be

beneficial if they are established with certain conditions like: -

- 1 They should take only a part of the profit to their country and provision should be made to invest some part of the profit in India itself.
2. Their interference in local politics should be stopped.
3. Natural resources should be allowed to be used with appropriate conditions.
- 4 They should also prepare items for the consumption of poor people.
- 5 They should also be motivated to fulfill social responsibilities.

2. सार्वजनिक उपक्रम के प्रकारों को बताएं तथा उनके बीच के अंतर को स्पष्ट करें।

उत्तर: संगठनात्मक दृष्टि से सार्वजनिक उपक्रम के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं:-

- A विभागीय उपक्रम
- B वैधानिक निगम
- C सरकारी कंपनी
- D बोर्ड द्वारा प्रबंध राजकीय उपक्रम
- E मिश्रित स्वामित्व वाली निगम

A विभागीय उपक्रम:- विभागीय उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम का वह रूप है जिसमें उपक्रम का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास रहता है और जिसका प्रबंध सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना के समय संपूर्ण वित्त की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है तथा इसकी समस्त आय ट्रेजरी में जमा होती है और इसके समस्त कार्यों का अंकेक्षण सरकार द्वारा कैग से करवाया जाता है।

B वैधानिक निगम:- वैधानिक /लोक निगम एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विशेष कानून के पारित होने से होता है उदाहरण के लिए L.I.C । इसकी सामान्य नीतियों का निर्धारण तो सरकार करती है लेकिन दिन प्रतिदिन के प्रबंधकीय और वित्तीय कार्यों में इसे काफी स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

C सरकारी कंपनी :- सरकारी कंपनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जिसकी स्थापना कंपनी कानून 1956 या 2013 के अनुसार हुआ हो और जिसकी कुल चुकता पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा दोनों में से किसी एक के पास हो। इस प्रकार सरकारी उपक्रम में सरकार एक अंशधारी बन जाते हैं।

D बोर्ड द्वारा प्रबंध राजकीय उपक्रम:- जब राजकीय उपक्रमों का प्रबंध निजी बोर्ड द्वारा होता है तो वह बोर्ड या समिति प्रबंधित राजकीय संस्था कहलाती है। इन समितियों या बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य लोच एवं शीघ्र निर्णय के गुण उत्पन्न करना है।

E मिश्रित स्वामित्व वाले निगम :- मिश्रित स्वामित्व वाले निगम का अर्थ उन संस्थाओं से है जिसमें सरकार आंशिक रूप से वित्त विनियोग करती है और प्रबंधन एवं

व्यवस्था का कार्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निजी क्षेत्र पर छोड़ देती है।

सार्वजनिक उपक्रम के विभिन्न प्रारूपण के मध्य अंतर

1 स्थापना:-

विभागीय उपक्रम सरकारी विभाग या मंत्रालय द्वारा स्थापित होते हैं।

वैधानिक निगम संसदीय विधानसभा या संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं। सरकारी कंपनी भारतीय कंपनी कानून 2013 के अनुसार स्थापित होती है।

2 पूंजी:-

विभागीय उपक्रम की पूंजी सरकार की बजट व्यवस्था द्वारा प्रदान की जाती है।

वैधानिक निगम में पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। सरकारी कंपनी में न्यूनतम 51% पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है बाकी निजी भागीदारी द्वारा लगाई जा सकती है।

3 उपयुक्तता:-

विभागीय उपक्रम जन उपयोगी, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए उपयुक्त है।

वैधानिक निगम औद्योगिक उपक्रमों के लिए उपयुक्त है। सरकारी कंपनी घरेलू एवं विदेशी निजी पूंजी की भागीदारी देने के लिए उपयुक्त है।

4 स्टाफ:-

विभागीय उपक्रम के सदस्य सरकारी कर्मचारी होते हैं। वैधानिक निगम के कर्मचारियों का चयन निगम द्वारा स्वयं किया जाता है।

सरकारी कंपनी के कर्मचारियों का चयन कंपनी द्वारा किया जाता है।

5 उदाहरण:-

विभागीय उपक्रम के उदाहरण हैं रेलवे, डाक विभाग।

वैधानिक निगम के उदाहरण हैं आरबीआई,आईडीबीआई ,एसबीआई

सरकारी कंपनी के उदाहरण हैं एचएमटी कोल इंडिया गेल।

Explain the types of public enterprises and explain the difference between them.

Ans: From the organizational point of view, public enterprises can be of the following types:-

- A Departmental Undertaking
- B Statutory corporation
- C Government company
- D Government undertaking managed by board
- E Mixed ownership corporation

A Departmental Undertaking:- Departmental Undertaking is that form of public undertaking

in which the full ownership of the undertaking remains with the government and which is managed by a ministry of the government. At the time of its establishment, the entire finance is arranged by the government and all its income is deposited in the treasury and all its works are audited by the government through CAG.

B Statutory Corporation:- Statutory / Public Corporation is an institution which is established by the passing of any special law of the Central or State Government, for example L.I.C. Its general policies are decided by the government but it enjoys considerable independence in day-to-day managerial and financial functions.

C Government Company:- Government company means a company which is established in accordance with the Companies Act 1956 or 2013 and in which at least 51% of the paid-up capital is held by the Central Government or State Government or either of them. The government becomes a shareholder in the government undertaking.

D Government Undertakings managed by Board:- When government undertakings are managed by a private board then it is called a board or committee managed government institution. The purpose of establishing these committees or boards is flexibility and to develop the qualities of quick decision.

E Mixed ownership corporations: Mixed ownership corporations mean those institutions in which the government partially invests the money and leaves the work of management and administration completely or partially to the private sector.

Difference between different types of PSU

1 Establishment:- Departmental undertakings are set up by a government department or ministry. Statutory corporation are established by special Act of parliament. The government company is established as per the Indian Companies Act 2013.

2 Capital:- The capital of departmental undertakings is provided by the budgetary provision of the government. In a statutory corporation the capital is provided by the government. In a government company, minimum 51% of the capital is invested by the government and the rest can be invested by private partnership.

3 Suitability:- Departmental undertaking is suitable for public utility, national security etc.

Statutory corporation is suitable for industrial undertakings. Government company is suitable for participation of domestic and foreign private capital.

4 Staff:- The members of departmental undertakings are government employees. The employees of a statutory corporation are selected by the corporation itself. Government company employees are selected by the company.

5 Example:- Examples of departmental undertakings are Railways, Postal Department. Examples of statutory corporations are RBI, IDBI, SBI. Example of government company is HMT, Coal India, GAIL.

3. सार्वजनिक क्षेत्र का क्या अर्थ है। सार्वजनिक क्षेत्र की बदली हुई भूमिका को बताएं।

उत्तर: सार्वजनिक उपक्रम का आशय किसी ऐसे औद्योगिक वाणिज्यिक या व्यावसायिक उपक्रम से है जिसका स्वामित्व प्रबंध और संचालन केंद्र राज्य या स्थानीय सरकार अथवा किसी अन्य लोक संस्था के अधीन हो।

समाज की आर्थिक क्रियाओं में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से काफी व्यापक रहा है। हम जानते हैं की, विवेकशील सरकार के सक्रिय सहयोग के बिना कोई भी देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। जन उपयोगी सेवाएं प्रदान करनी हो, रोजगार बढ़ाना हो, आर्थिक विकास को तेज करना हो, संतुलित औद्योगिक विकास करना हो, एकाधिकार अधिकार प्रवृत्ति पर रोक लगानी हो, राष्ट्रीय संसाधनों का उचित प्रयोग करना हो ये सभी के लिए सार्वजनिक उपक्रम को स्थापित करना आवश्यक हो जाता है।

सार्वजनिक उपक्रम के कई प्रकार हो सकते हैं

- A विभागीय संगठन
- B लोक निगम
- C सरकारी कंपनी
- D बोर्ड द्वारा प्रबंध राजकीय उपक्रम
- E मिश्रित स्वामित्व वाले निगम

सभी प्रकार के संगठनों के अपने-अपने ने गुण दोष हैं तथा किसी को भी अलग-अलग स्थिति तथा जरूरी आवश्यकता के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र का बदलता स्वरूप या भूमिका

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कई वर्षों से व्यापक परिवर्तनों से होकर गुजर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो 1948 से 1990 तक निरंतर विस्तार एवं विकास कर रहे थे अब सिकुड़ने लगे हैं। अब यह महसूस किया जाने लगा है कि सरकार की जिम्मेदारी अब औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में कम तथा देश को सुरक्षित बनाए रखने एवं कुशल शासन प्रदान करने में अधिक हो गई है।

भारत सरकार ने जुलाई 1991 में अपनी नई आर्थिक

नीति की घोषणा की इस नीति में सार्वजनिक उपक्रम के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को 17 से घटकर अब तीन कर दी गई।

2 बीमार या घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों का विनिवेश किया जाएगा।

इसके पश्चात से सरकार निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा नए क्षेत्रों में पूंजी लगाने को प्रेरित कर रही है। वर्तमान में निजी क्षेत्र को रक्षा के उपकरण बनाने तक का कार्य भी मिल गया है। अब सार्वजनिक क्षेत्र का केवल रेल एवं अणुशक्ति में ही एकाधिकार रह गया है। वैसे सार्वजनिक उपक्रम जो महत्वपूर्ण क्षेत्र के नहीं हैं और बीमार चल रहे हैं उनका तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में नए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। साथ ही पुराने कर्मचारियों को भी अवकाश ग्रहण योजना (VRS) के तहत कम किया जा रहा है।

यदि सार्वजनिक उपक्रमों को जीवित करना है तो पेशेवर प्रबंधकों को लाना होगा, राजनीतिक एवं नौकरशाही का हस्तक्षेप समाप्त करना होगा और विनिवेश के समय अंश निजी क्षेत्र को न बेचकर आम जनता को बेचना होगा।

What is mean by public sector? Explain the changed role of public sector.

Ans: Public undertaking means any industrial, commercial or business undertaking whose ownership, management and operation is under the central, state or local government or any other public institution.

The contribution of the public sector in the economic activities of the society has been quite extensive since independence. We know that no country can achieve economic development without the active support of a prudent government. To provide public utility services, to increase employment, to accelerate economic development, to have balanced industrial development, to stop monopoly tendencies, to make proper use of national resources, it becomes necessary to establish a public enterprise.

There can be many types of public enterprises

A Departmental organization

B Public Corporation

C Government company

D Government undertaking managed by board

E Mixed ownership corporations

All types of organizations have their own merits and demerits and any one is established by the government according to the different situation and urgent need.

Changing nature or role of public sector

The role of the public sector in India has been undergoing extensive changes over the years. Public sector enterprises which were continuously expanding and developing from 1948 to 1990 have now started shrinking. It is now being realized that the responsibility of the government is now less in the industrial and commercial sectors and more in keeping the country safe and providing efficient governance.

The Government of India announced its new economic policy in July 1991. In this policy the following decisions were taken for public enterprises: -

1 Industries reserved for the public sector were reduced from 17 to 3.

2 Shares of sick or loss making public enterprises will be disinvested.

After this, the government is encouraging the private sector to invest in new areas. At present, the private sector has also got the work of manufacturing defense equipment. Now the public sector has a right only in railways and nuclear power. However, public enterprises which are not in the critical sector and are running sick are being rapidly privatized. New employees are not being appointed in the public sector. Besides, old employees are also being reduced under the Voluntary Retirement Scheme (VRS).

If public enterprises have to be revived, professional managers will have to be brought in, political and bureaucratic interference will have to be eliminated and at the time of disinvestment, the share of the public sector will have to be sold to general public instead of private sector.